संपादकीय

''नए शिक्षा सत्र से पहले राजस्थान में प्रारंभिक शिक्षा की यह डरावनी खबर है कि मौजूदा भाजपा सरकार के कार्यकाल में पिछले तीन शिक्षा सत्रों में 15,294 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। खामियाजा यह हुआ कि सरकारी स्कूलों में ढाई लाख बच्चे घट गए और सरकार के इस फैसले का फायदा निजी स्कूलों को मिला। इस दौरान 1,122 निजी स्कूल बढ़ गए हैं और निजी स्कूलों में बच्चों की तादाद भी 1,11,000 बढ़ गई। तीन सत्रों में राज्यभर में 847 सरकारी गर्ल्स स्कूलों पर भी ताले लटक गए। ...प्रदेश में तीन शिक्षा सत्रों में सर्वाधिक 14297 अस्तित्व खोने वाले पांचवीं कक्षा तक के प्राथमिक स्कूल और शेष उच्च प्राथमिक स्कूल हैं।''[1]

''...नीति आयोग का मानना है कि देश में पढ़ाई-लिखाई के लिहाज से खराब स्तर वाले सरकारी स्कूलों को निजी हाथों को सौंप दिया जाना चाहिये। आयोग का मानना है कि ऐसे स्कूलों को सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत निजी कंपनियों को दे दिया जाना चाहिए।''[2]

दोनों खबर हमें हमारी सार्वजनिक शिक्षा के स्वास्थ्य की खस्ताहालत के बारे में पर्याप्त संकेत देती हैं। और साथ ही हमारी सरकारों की मंशा को भी हमारे सामने रख देती हैं। एक ऐसे समय में जब हम अपने को दुनिया की सबसे ज्यादा युवा आबादी वाला देश कहते नहीं थक रहे यह थकी हुई शिक्षा व्यवस्था उस युवा आबादी के सपनों में सिवाय हताशा के और कौनसा रंग भर सकने में समर्थ है यह समझना मुश्किल नहीं है।

एक गाना याद आता है- ''नन्हे-मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है/...आने वाली दुनिया में सबके सर पे ताज होगा/ना भूखों की भीड़ होगी, ना दुखों का राज होगा/बदलेगा ज़माना ये सितारों पे लिखा है/नन्हे-मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है'' (फिल्मः बूट पॉलिश, गीतकारः शैलेन्द्र, संगीतः शंकर-जयकिशन, सनूः 1954)

यह गीत उन सपनों का का गीत है जो हाल ही में आजाद हुआ एक समाज देख रहा था। संविधान को लागू हुए बमुश्किल 5 साल भी नहीं हुए थे। आजादी नाम की चिड़िया के पंखों में एक किस्म की नई-नई रवानी थी। इस गीत में एक बेहतर कल का सपना है, एक ऐसा कल जिसमें लोकतंत्र फलेगा-फूलेगा। सत्ता में लोगों की भागीदारी होगी, सबको न्याय मिलेगा। वर्तमान दशा बदलेगी। यह आजादी की पौ-फटने के बाद का समय था। लोगों में बनते हुए भारत से एक उम्मीद थी।

आज आजादी के 70 साल बाद की टोह लेते हैं तो उक्त खबरों के रूप में हताशा हमारे सामने मुंह बाए खड़ी दिखती है। लोगों को अब राज्य से उम्मीद की जगह नाउम्मीदी है और राज्य भी ऐसा करते हुए दिखने में अपना योगदान देने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाह रहा है। यह दोनों खबर हमें राज्य के बदलते चरित्र के बारे में बताती हैं। अब राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी अपनी उन सभी जिम्मेदारियों का बोझ हल्का करना चाहता है जो आजादी के समय में एक लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना के तहत उसने अपनी समझी थीं और इस बोझ को इस तरह उतारना चाहता है कि किसी तरह का कोई 'गिल्ट' उसके हिस्से ना आए। इसके लिए निजीकरण को वह अपने ही एक बेहतर विकल्प के रूप में पेश करने पर तुला है।

लोकतंत्र के फलने-फूलने का एक रास्ता शिक्षा से होकर गुजरता है। शिक्षा से यह उम्मीद की जाती है कि वह एक बदलावकारी भूमिका निभाएगी और लोगों में एक स्वायत्त व जिम्मेदार नागरिक की चेतना विकसित करेगी। वह समाज में मौजूद विषमता को समाप्त करेगी। मगर जो शिक्षा व्यवस्था स्कूलों की विभिन्न श्रेणियों के रूप में खुद कई विषमताओं से घिरी हो उससे यह उम्मीद करना बेमानी है। विषमता के इस दायरे में राज्यों द्वारा संचालित स्कूल अब सबसे निचले पायदान पर आने लगे हैं। राज्यों के सरकारी स्कूलों की तस्वीर आज हमारे मन में एक ऐसी जगह के रूप में उभरती है जिसके पास ठीक से कोई इमारत नहीं होगी, शौचालय नहीं होंगे, पानी व लाइट की ठीक से व्यवस्था नहीं होगी, पूरी संख्या में शिक्षक नहीं होंगे जो होंगे भी वे खुद अपनी ही हताशाओं से घिरे होंगे।

सवाल यह है कि क्या यह समस्या अचानक इतनी विकराल हो गई? नहीं इसे धीरे-धीरे इस स्थिति में पहुंचाया गया है। एक समय में पैरा टीचर नियुक्त करके, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खोलकर सार्वजनिक शिक्षा ने उस मध्यम व उच्च मध्यम वर्ग का भरोसा खोया जो अपने हकों की आवाज ज्यादा बुलंदी के साथ उठाने में समर्थ था। आज स्थिति यह है कि सरकारी विद्यलयों में मध्यम वर्ग सिर्फ नौकरी करता है अपने बच्चों को पढ़ाता नहीं है। इसका परिणाम यह हुआ कि आज आए दिन समायोजन के नाम पर सरकारी स्कूल बंद कर दिए जाने के बावजूद यह घटना किसी तरह की कोई खबर नहीं बनती। अकेले राजस्थान में पिछले तीन वर्षों में पन्द्रह हजार से ज्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं और आप पाएंगे कि अखबारों में इस खबर को पन्द्रह कॉलम तक नहीं मिले। और यह ऐसा रास्ता है जिस पर अन्य राज्य सरकारें भी सरपट दौड़ने की तैयारी कर चुकी हैं। जब नीति आयोग खुद सरकारी स्कूलों को निजी कम्पनियों को दे देने की सिफारिश कर रहा हो तो राज्य क्यों नहीं इस जिम्मेदारी से अपना पल्ला झाड़ने को तैयार होंगे। राजस्थान इस तरह के प्रयोगों के लिए इस समय सबसे उपजाऊ साबित हो रहा है,''वसुंधरा राजे सरकार ने राजकीय स्कूलों को निजी क्षेत्र में देने का फैसला कर लिया है। इसके लिए बाकायदा ''स्कूली शिक्षा में PPP नीति-2017'' का मसौदा तैयार किया गया है। कैबिनेट ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। पहले चरण में राज्य की 300 स्कूलों को निजी भागीदारों को सौंपा जाएगा। निजी भागीदार सरकारी स्कूलों की जमीन, इमारत और अन्य सुविधाओं का इस्तेमाल करेगा लेकिन उसे स्टाफ की व्यवस्था खुद करनी होगी। इन स्कूलों में लगे शिक्षकों को दूसरी सरकारी स्कूलों में समायोजित कर दिया जाएगा।''[3] इस खबर से पता चलता है कि स्कूलों की ओर निजी क्षेत्र मुत में आकर्षित नहीं होने वाला वह उनकी **''जमीन, इमारत व अन्य सुविधाओं का इस्तेमाल करेगा।''** (बल अतिरिक्त) और शिक्षकों के वेतन पर खर्च करने की जो जिम्मेदारी आने वाली थी उससे उसे यह कह कर मुक्त कर दिया गया है कि **''उसे स्टाफ की व्यवस्था खुद करनी होगी।''** (बल अतिरिक्त) राज्य सरकार के इस सरोकार पर आप सिवाय मुग्ध होने के और कर ही क्या सकते हैं। यानी राज्य ने पूरे वेतन पर शिक्षक रखने की जिम्मेदारी से निजी क्षेत्र को मुक्त कर दिया है। अब वह औने-पौने दाम पर कैसे भी शिक्षक भर्ती करने व उनसे कैसे भी काम लेने के लिए स्वतंत्र है। इसका एक और पक्ष है कि जैसे-जैसे यह मॉडल अपने पैर पसारेगा वैसे-वैसे यह शिक्षकों के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा करेगा। यह सार्वजनिक संपदा को निजी हाथों में सौंपने का खेल है जिसे शिक्षा की बेहतरी के नाम पर खेला जा रहा है। और इसके खिलाफ किसी तरह की कोई आवाज न तो शिक्षक संघों की तरफ से और न ही दूसरे किन्हीं पक्षों की तरफ से उठती दिख रही है।

यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि सबसे ज्यादा संख्या में प्राथमिक स्कूल बंद हुए हैं। यह उम्र ऐसी होती है जब बच्चा बहुत दूर स्कूल नहीं जा पाता। इस बात का असर पिछड़े व दलित बच्चों पर पड़ना निश्चित है, खासकर लड़कियां सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली हैं। आंकड़े यह बताते हैं कि यही वे कक्षाएं भी हैं जब सबसे ज्यादा बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। स्कूल का हताश कर देने वाला व बच्चे की उमंगों को कुचल देने वाला माहौल जैसे- अकेले शिक्षक के भरोसे चलता स्कूल, या शिक्षक का व्यवहार, स्कूली पाठ्यचर्या की विषयवस्तु की बच्चे के जीवन से दूरी आदि मिलकर बच्चे और सीखने के बीच एक अभेद्य दीवार का काम करते हैं। ऊपर से स्कूल का दूर होना यह सब बच्चे को स्कूल छोड़ देने को ही अधिक प्रेरित करने वाले कारक हैं।

खबर का एक अंश बताता है कि सरकारी स्कूलों के बन्द होने के साथ-साथ निजी स्कूलों की संख्या व उनमें बच्चों की संख्या दोनों में बढ़ोतरी हुई है। यह इस बात का संकेत है कि लोगों को आज शिक्षा से उम्मीदें बहुत हैं इसके लिए वे अपनी सीमित आमदनी में से भी खर्च करने को तैयार हैं। बस शिक्षा ही उनकी उम्मीदों पर उतनी खरी नहीं उतर पा रही जितनी कि उससे उम्मीद की जा रही है। ◆

संदर्भ

1. https://www.bhaskar.com/news/RAJ-BIK-MAT-latest-bikaner-news-025503-2435930-NOR.html
2. http://navbharattimes.indiatimes.com/business/business-news/recommend-to-submit-government-schools-with-poor-condition-of-private-policy/articleshow/60278196.cms
3. http://hindi.firstpost.com/india/rajasthan-government-schools-to-be-privatized-ps-52325.html